स्थापना : 1997 - संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -15 ■ अंक - 350 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 दिसंबर 2016 ■ पेज - 12 ■ मूल्य 5 रु.

डीआरएम को शिफ्ट करना समस्या का समाधान नहीं

सुरेश त्रिपाठी

रविवार, 20 नवंबर 2016 को दो बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुईं. पहली भीषण दुर्घटना में कानपुर देहात के पुखरायां-मलाशा सेक्शन के बीच गाड़ी संख्या 19321 इंदौर-राजेंद्रनगर एक्सप्रेस सुबह करीब 3.04 बजे बुरी तरह डिरेल हुई. झांसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत हुई इस दुर्घटना में लगभग 150 से ज्यादा निरीह-निर्दोष यात्रियों की मौत हुई और करीब 300 यात्री घायल हुए. दूसरी बड़ी घटना रायपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टिल्डा-रायपुर सेक्शन के बीच एक मालगाड़ी डिरेल होने की हुई. यह दुर्घटना भी सुबह के ही समय हुई, जिससे दोनों अप-डाउन लाइनें दिनभर के इए ब्लॉक हो गईं. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर यह दुर्घटना शेष पेज 4 पर...

सीआरबी को मजबूत करने से बैठ रहा है भारतीय रेल का भट्टा

■ डीजी/स्टोर्स, डीजी/एसएंडटी और डीजी/कार्मिक की नियुक्ति

■ डीजी/स्टोर्स और डीजी/ एसएंडटी सीआरबी के, तो डीजी/कार्मिक एमएस के मातहत क्यों?

नई दिल्ली : पिछले हफ्ते महानिदेशक/भंडार (डीजी/स्टोर्स) के पद पर पूर्व महाप्रबंधक/द.पू.रे. ए. के. गोयल और महानिदेशक/संकेत एवं दूरसंचार (डीजी/एसएंडटी) के पद पर पूर्व महाप्रबंधक/म.रे. अखिल अग्रवाल तथा महानिदेशक/कार्मिक (डीजी/कार्मिक) के पद पर पूर्व एडीशनल मेंबर/स्टाफ आनंद माथुर की पोस्टिंग रेलवे बोर्ड में की गई है. एक तरफ रेलवे बोर्ड में अधिकारियों के पद कम करने के बजाय लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनमें भीषण विसंगति भी शेष पेज 7 पर...

चौबीस घंटों में भी एक्सीडेंट साइट क्लियर नहीं करा पाए डीआरएम/रायपुर

■ लापरवाह डीआरएम/ रायपुर को भी क्यों नहीं हटाया गया?
■ इस बार मालगाड़ी डिरेलमेंट का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेंगे डीआरएम/ रायपुर?
■ दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंचे मौज-मस्ती में डूबे महाप्रबंधक/द.पू.म.रे.

रायपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में टिल्डा और रायपुर सेक्शन के बीच रविवार, 20 नवंबर को एक मालगाड़ी पूरी तरह से पलट गई. इससे प्रॉपर पन्क्चुअलिटी मेनटेन करने और डिरेलमेंट न होने देने का दम भरने वाले डीआरएम/रायपुर की पूरी कलई तब खुल गई, जब वह चौबीस घंटों में भी साइट क्लियर नहीं करा पाए. जबकि उधर पुखरायां में हुई भीषण दुर्घटना, जिसमें 150 से ज्यादा यात्री मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए, की साइट 9 घंटे में क्लीयर हो गई और जीएम/उ.म.रे. भी लगातार साइट पर उपस्थित रहे. मगर टिल्डा-रायपुर के बीच पलटी मालगाड़ी के दुर्घटना शेष पेज 7 पर...

चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में रेलवे की

आय में भारी गिरावट

■ रेलवे बोर्ड की बचकानी नीतियों के चलते रेलवे को 32.9 अरब का नुकसान
■ माल ढुलाई में लगातार आ रही कमी के कारण घाटे में जा रही है भारतीय रेल

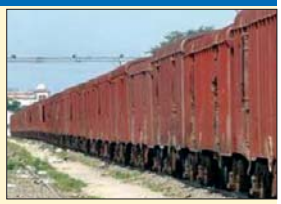

नई दिल्ली : रेलमंत्री सुरेश प्रभु के बचकाने सलाहकारों की सलाह और बचकानी नीतियों तथा 'स्टोरकीपर' सीआरबी की रेलवे के तकनीकी मामलों में अनभिज्ञता के कारण पिछले वर्ष की पहली छमाही की अपेक्षा चालू वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दरम्यान भारतीय रेल की आय में कुल करीब 32.9 अरब रुपए की भारी गिरावट आई शेष पेज 7 पर...

प्रधानमंत्री द्वारा रेल सड़क पुल तथा दोहरीकरण का शिलान्यास

गोरखपुर ब्यूरो

■ प्रधानमंत्री द्वारा गाजीपुर-कोलकाता शब्दभेदी साप्ता. सुपरफास्ट एक्स. का उद्घाटन
■ नवनिर्मित पेरिशेबल कार्गो सेंटर का लोकार्पण, मऊ-ताड़ीघाट नई लाइन का उदघाटन
■ 'भोजपुरी' में बोलते प्रधानमंत्री को सुनकर झूम उठी गाजीपुर की जनता

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाजीपुर के आरटीआई ग्राउंड पर आयोजित भव्य समारोह में हरी झंडी दिखाकर 14 नवंबर को नई गाड़ी शब्दभेदी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गाजीपुर सिटी-कोलकाता साप्ताहिक) को रवाना किया गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा फलक का अनावरण कर गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पेरिशेबल कार्गो सेंटर का लोकार्पण, मऊ-ताड़ीघाट नई रेलवे लाइन परियोजना का उदघाटन, गाजीपुर के समीप गंगा नदी पर नए रेल-सड़क पुल एवं गाजीपुर सिटी-बलिया रेल खंड के दोहरीकरण का शिलान्यास भी किया गया.

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, रेल राज्यमंत्री एवं संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र शेष पेज 6 पर...

सीआरबी ने त्रिची मंडल के 4 टीटीई का इंटर डिवीजन ट्रांसफर रोका

सुरेश त्रिपाठी

कुछ समय पहले चर्चा थी कि रेलवे बोर्ड के एक मेंबर ने दक्षिण रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सीसीएम) का ट्रांसफर करने के लिए यूनियन से 10 करोड़ रुपए की सुपारी ली है. यह चर्चा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि बताया गया कि सीसीएम को रेलवे बोर्ड में बुलाकर उक्त मेंबर ने यह तक कह दिया कि चेन्नई जाकर अन्यत्र पोस्टिंग पर जाने की तैयारी करो, पोस्टिंग/ट्रांसफर ऑर्डर आपके पहुंचने से पहले चेन्नई पहुंच जाएगा. बहरहाल, बाद में पता चला कि एक ईमानदार व्यक्ति के हस्तक्षेप और रेलमंत्री तक इस चर्चा को पहुंचा दिए जाने से तब सीसीएम का ट्रांसफर ऑर्डर तो नहीं किया जा सका, मगर अब ऐसा लगता है कि वह 10 करोड़ की सुपारी सीआरबी तक पहुंचा दी गई है? क्योंकि सीआरबी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे के अप्रूवल से तिरुचिरापल्ली मंडल के जिन चार महाभ्रष्ट यूनियन पदाधिकारियों का इंटर डिवीजन ट्रांसफर 11 नवंबर को किया गया था, उसे सीआरबी ने रेलवे बोर्ड से एक पत्र (सं.2016/ई(एलआर)3/आरईएफ/एआईआरएफ/5, दि. 22.11.2016) जारी करवाकर रद्द कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि त्रिची मंडल के जिन चार कर्मचारियों या यूनियन पदाधिकारियों का इंटर डिवीजन ट्रांसफर किया गया था, उनमें सीपीसी/सीपीएसआर/ओ/त्रिची एफ. एक्स. इसाक जॉनसन, सीटीआई/स्टेशन/त्रिची एम. थमारी सेल्वन, टीटीआई/स्टेशन/मालावरम बी. जयचंद्रन और सीएंडआरएस/त्रिची एस. जेड. सैय्यद ताजुद्दीन शामिल थे. दक्षिण

- यदि अकर्मण्य रेलवे बोर्ड का होता रहा ऐसा हस्तक्षेप, तो कैसे सुधरेगा रेल प्रशासन?
- भ्रष्ट कर्मचारियों को सीआरबी ने दिया और अधिक उद्दंड और भ्रष्ट होने का लाइसेंस
- सीआरबी के इस अवैध हस्तक्षेप से यूनियन पदाधिकारी अब और ज्यादा होंगे निर्द्वंद
- सीसीएम को ट्रांसफर न करा पाने के बदले क्या यूनियन से 10 करोड़ में हुआ यह सौदा?
- सीबीआई द्वारा अनुशंसित 41 टीटीई का भी इंटर डिवीजन ट्रांसफर क्या रोक लेंगे सीआरबी?

रेलवे मुख्यालय से यह आदेश 11 नवंबर को जारी किया गया था. इसके तत्काल बाद उसी दिन चारों का लोकल ऑर्डर भी त्रिची मंडल से निकाला गया था. परंतु उपरोक्त चारों कर्मचारियों ने ट्रांसफर ऑर्डर स्वीकार नहीं किया था और अंडरग्राउंड हो गए थे. तथापि मंडल प्रशासन की तरफ से मस्टर से उनका नाम हटा दिया गया था और उनके ट्रांसफर ऑर्डर उनके घरों में चिपका दिए गए थे. अब सीआरबी की मेहरबानी से बताते हैं कि उक्त चारों कर्मचारी सीना तानकर त्रिची में घूम रहे हैं.

कहने को तो सीआरबी ने उक्त चारों कर्मचारियों अथवा यूनियन पदाधिकारियों

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2016/E(LR)III/REF/AIRF/5 New Delhi-110 001, Dated: 22.11.2016

The General Manager,
Southern Railway,
Chennai.

Sub: Inter-divisional transfer of office bearers of SRMU from Tiruchirappalli(TPJ) Division to other divisions issued vide Letter No.P(L)694/IV/I/Complaint/TPJ (Pt.) dated 11.11.2016.

****

In the abovementioned matter, General Secretary/AIRF vide letter No. AIRF/76 dated 14.11.2016 addressed to CRB has represented against the transfer of the four office bearers of TPJ division of SRMU.

After reviewing the matter, Board has decided to pend the inter-divisional transfer orders (issued vide Southern Railway's Letter No.P(L)694/IV/I/Complaint/TPJ (Pt.) dated 11.11.2016) for a period of six months from the date of issue of these orders.

(Naveen Kumar)
Deputy Director, E(LR)I
Railway Board

के इंटर डिवीजन ट्रांसफर को छह महीने के लिए 'पेंड' किया है, मगर इसका दक्षिण रेलवे के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों में बहुत खतरनाक संदेश गया है. जबकि यूनियन की बांछें खिल गई हैं. कई अधिकारियों का कहना है कि सीआरबी का यह अवैध हस्तक्षेप महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे का भारी अपमान है, क्योंकि उनके आदेश से ही उक्त कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया था. ऐसे में यदि कोई जोनल महाप्रबंधक अपने मातहत कर्मचारियों को अनुशासित करने का कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो उसके महाप्रबंधक होने का क्या अर्थ रह जाता है? उनका यह भी कहना है कि सीआरबी के इस तथाकथित 'पेंड ऑर्डर' का मतलब यह है कि तब तक सीसीएम (मार्च में) रिटायर हो जाएंगे अथवा उससे पहले उन्हें कहीं अन्यत्र नियुक्त कर दिया जाएगा. उसके बाद दक्षिण रेलवे में यूनियन का साम्राज्य पूर्ववत स्थापित हो जाएगा. यही उक्त 'पेंड ऑर्डर' की असली मंशा है, क्योंकि यहां एसडीजीएम, सीपीओ, सीओएम इत्यादि जैसे यूनियन के जरखरीद गुलाम पहले से ही ऐसी ही मंशा लिए बैठे हुए हैं, जिन्हें अन्य जोनल रेलों में ट्रांसफर करने की हिम्मत

Southern Railway

Headquarters Office,
Personnel Department,
Chennai-600 003.

No. P(L)694/IV/I/Complaint/TPJ (pt.). Dated: 11-11-2016.

DRM/TPJ

Sub: Transfer of Office Bearers of SRMU on Administrative grounds - TPJ Division.

Ref: DRM/TPJ's letter No. DRM/PPS/2016/GENL dated 17-10-2016.

The competent authority, i.e. the General Manager, has examined the subject issue and approved for transfer of the following office bearers of Southern Railway Mazdoor Union (SRMU) of TPJ division on administrative grounds:

1. Shri F.X. Isac Johnson, CPC, CPSR/O/TPJ transferred to MDU division
2. Shri V. Thamaraiselvan, TTI/Station/TPJ transferred to SA division
3. Shri B. Jayachandran, TTI/Station/MV transferred to MAS division
4. Shri S.Z. Syed Thajudeen, C&RS/TPJ transferred to MDU division

Necessary further action may be taken.

(Shanthi Rajabhoj)
Dy Chief Personnel Officer/Labour
For General Manager

रेलवे बोर्ड या सीआरबी नहीं जुटा पा रहे हैं?

अब सवाल यह उठता है कि क्या सीआरबी अथवा रेलवे बोर्ड में इतना साहस है कि वह चेन्नई मंडल के उन 41 टीटीई का भी इंटर डिवीजन ट्रांसफर रोक सकते हैं, जिसकी अनुशंसा सीबीआई ने की है? विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब सीबीआई ने यह अनुशसा दक्षिण रेलवे के एसडीजीएम के पास यह कहकर भेजी थी कि जांच के दौरान इन 41 भ्रष्ट कर्मचारियों के मंडल में रहते कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए इन सभी का तत्काल इंटर डिवीजन ट्रांसफर किया जाना चाहिए. तब एसडीजीएम ने पहले तो उक्त अनुशंसा को अपने पास काफी दिन तक दबाए रखा और इस बीच यूनियन से महाप्रबंधक के नाम एक पत्र लिखवाया कि रेलवे की तरफ से सीबीआई को लिखा जाए कि जांच में तेजी लाए और इस प्रकार के ट्रांसफर नहीं किए जाने चाहिए.

सूत्रों का कहना है कि एसडीजीएम ने सीबीआई की उक्त अनुशंसा पर बिना कोई टिप्पणी लिखे ही फाइल को सीपीओ के पास भेज दिया. बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का एक साथ इंटर डिवीजन ट्रांसफर किए जाने की इबारत देखते ही सीपीओ के हाथ-पांव फूल गए, और उन्होंने उक्त फाइल यह लिखकर महाप्रबंधक के पास भेज दी कि उस पर उनकी अनुमति/अप्रूवल आवश्यक है. पता चला है कि महाप्रबंधक उक्त फाइल देखकर ही समझ गए कि एसडीजीएम और सीपीओ दोनों यूनियन के खैरख्वाह बने रहने के लिए यह सारा खेल कर रहे हैं. उन्होंने उस फाइल पर एसडीजीएम की टिप्पणी आवश्यक लिखकर फाइल पुनः एसडीजीएम के पास वापस भेज दी.

बताते हैं कि इसके बाद चालाक एसडीजीएम ने पहले संबंधित डिप्टी सीवीओ से उक्त फाइल पर वाजिब टिप्पणी लिखवाई और फिर खुद उस पर यह लिखकर कि चूंकि मामला सीबीआई की अनुशंसा का है, इसलिए महाप्रबंधक इस पर अपनी सहमति दें, और फाइल पुनः महाप्रबंधक के पास भेज दी. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार महाप्रबंधक ने फाइल पर लिखा कि यदि सीसीएम चाहें तो कुछ समय तक के लिए उक्त कर्मचारियों को सीबीआई से मोहलत दिला दें और सीबीआई को अपनी जांच तेज करने के लिए भी कहें, या फिर वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उक्त सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर किए जाने की यथोचित कार्यवाही करें. यानि हर अधिकारी ने फाइल पर जलेबियां बनाने की पूरी कोशिश की और अंततः सारा दारोमदार सीसीएम के सिर मढ़ दिया गया है. तथापि सूत्रों का कहना है कि उक्त 41 कर्मचारियों का इंटर डिवीजन ट्रांसफर रोकने की किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई भी सीबीआई के विरुद्ध नहीं जाना चाहेगा और उक्त ट्रांसफर अगले कुछ दिनों में हो सकते हैं.

'रेलवे समाचार' के ब्यूरो प्रमुख/इलाहाबाद उमेश शर्मा को पत्नी शोक

प्रधानमंत्री की पूरे देश में नोटबंदी की घोषणा और उससे उपजी समस्या के कारण अब तक देश भर में करीब 70-80 लोगों की कीमती जानें अकारण चली गईं हैं. इसी समस्या के चलते कुछ अर्से से कैंसर से पीड़ित ममता शर्मा को भी असमय जाना पड़ा है. उनकी आकस्मिक मृत्यु सोमवार, 21 नवंबर को सुबह करीब 6 बजे चिरगांव, झांसी में हुई. स्व. ममता शर्मा एक धर्म-परायण एवं अत्यंत संस्कारी महिला होने के साथ ही 'रेलवे समाचार' के ब्यूरो प्रमुख/इलाहाबाद उमेश शर्मा की पत्नी थीं. श्री शर्मा ने बताया कि 18 नवंबर को वह ममता को लेकर ग्वालियर गए थे, जहां पहले से उनका इलाज चल रहा था, मगर इस बार अस्पताल ने पुराने नोट लेने और उसके कारण ममता को भर्ती करने से मना कर दिया, मजबूरीवश उन्हें चिरगांव वापस लेकर आना पड़ा और अगले ही दिन वह अपने एक बेटे और दो बेटियों को बिलखता छोड़कर चली गईं. ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा की शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना.

नुक्कड़ नाटक के जरिए यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास

इलाहाबाद : इलाहाबाद जंक्शन के यात्री विश्रामालय हॉल में माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमेटिक संस्था के सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रियों को उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने, स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने, जहरखुरानी से बचाव, यात्रा के दौरान जरुरतमंदों की मदद, गर्भवती महिलाओं, बीमार एवं वरिष्ठ नागरिकों को सीट प्रदान करना, उनकी सहायता करना तथा मानव रहित रेलवे क्रासिंग को पार करते समय सावधानी बरतने हेतु यात्रियों को जागरुक करने का प्रयास किया गया. इस नुक्कड़ नाटक में अभिषेक बसाक, शिव शंकर, तस्लीम आरिफ, राघव, श्रेया, अजहर शाहिद, रितु, नवीला आदि कलाकारों ने भाग लिया.

इस अवसर पर स्टेशन प्रबन्धक राजाराम राजपूत, सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, एस. के. श्रीवास्तव, सीएचआई आर.के. राय, सीआईटी डोरी लाल शर्मा सहित कर्मचारीगण एवं यात्रीगण बड़ी संख्या उपस्थित रहे.

पी. पी. गेरा को श्रंद्धांजलि

अंत तक अपने काम और अपने साथियों के बीच लगातार सक्रिय रहे पी. पी. गेरा उर्फ प्रेम गेरा अब हमारे बीच नहीं रहे. 31 अक्टूबर 2016 को अचानक हुए हृदयाघात से उनका देहावसान हो गया. 24 जनवरी, 1949 को हरिद्वार में जन्में स्व. गेरा वर्ष 1975 में भारतीय रेल में आए थे. वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त होने से पहले वह काफी समय तक रेलमंत्री सेल और रेलवे बोर्ड में बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी/जनरल और डायरेक्टर/जनरल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे. सेवानिवृत्ति के बाद स्व. गेरा अपने अंतिम समय तक सी-ट्रैम में पहले जनरल मैनेजर और बाद में बतौर सलाहकार काम करते रहे. स्व. गेरा अपने साथियों के बीच और रेलवे में अपने मिलनसार स्वाभाव के कारण हमेशा लोकप्रिय रहे. उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में रेलवे बोर्ड के कई पूर्व मेंबर्स और महाप्रबंधकों सहित सैकड़ों की संख्या में रेल अधिकारी शामिल थे. ईश्वर उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना.

बिलासपुर अस्पताल में अवैध रूप से जारी है

आरपीएफ जवानों का डिकैटेगराइजेशन

बिलासपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित केंद्रीय रेलवे हॉस्पिटल में आरपीएफ जवानों को मेडिकली अनफिट करके डिकैटेगराइज करने और उन्हें सुविधाजनक पदों पर पदस्थ किए जाने का गोरखधंधा आजकल बहुत जोरों पर चल रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में कई बल सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा निदेशक/द.पू.म.रे. को कई बार बेनामी पत्र लिखकर अवगत कराया है, परंतु उन्होंने इस बारे में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है. परिणामस्वरूप कुछ बल सदस्यों ने उक्त पत्र 'रेलवे समाचार' को भेजकर बिलासपुर केंद्रीय रेलवे अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा चलाए जा रहे इस तमाम गोरखधंधे की जानकारी दी है. इसके अलावा 'रेलवे समाचार' द्वारा खुद जब इस संबंध में पूछताछ की गई, तो उक्त पत्रों में लिखी गई लगभग सभी बातें सही पाई गई हैं और तमाम बल सदस्यों ने इसकी पुष्टि भी की है.

पता चला है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय, बिलासपुर के कुछ कांट्रेक्ट डॉक्टर और विभागीय सीनियर डीएमओ/ओपीडी, जो कि एक सायक्याट्रिस्ट हैं, की मिलीभगत से आरपीएफ कर्मियों से बड़े पैमाने पर मोटी-मोटी राशि के कथित लेनदेन से उन्हें बिना उचित कारण के मेडिकली अनफिट करके डिकैटेगराइज किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार कांस्टेबल आर. पी. जांगड़े से कथित रूप से मोटी राशि लेने के बाद सीनियर डीएमओ द्वारा उसकी स्क्रीनिंग में खुद बैठकर उसे सुपरनुमेरेरी पोस्ट पर पदस्थापित करने में मदद की गई, जबकि उसी के साथ मेडिकली अनफिट होकर डिकैटेगराइज हुए दो अन्य बल सदस्यों को ग्रेड-पे 1800 में रखकर सफाईवाला बना दिया गया, क्योंकि वह दोनों सीनियर डीएमओ को उनकी मुंहमांगी रकम नहीं दे पाए थे. बताते हैं कि एक कांट्रेक्ट डॉक्टर लालचंदानी द्वारा अपने निजी स्थानीय अस्पताल के लिए कथित रिश्वत के रूप में एसी, एलसीडी, कंप्यूटर इत्यादि महंगी चीजें मांगी जाती हैं.

इसी प्रकार कथित रूप से मोटी रकम लेकर मात्र पांच साल की सर्विस वाले एक सब-इंस्पेक्टर आशुतोष तिवारी को मेडिकली अनफिट घोषित किया गया है. बताते हैं कि इसी तरह एक महा-नौटंकीबाज महिला कांस्टेबल को भी जल्द से जल्द अनफिट किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. बताते हैं कि इस महिला कांस्टेबल को अनफिट करने के लिए दो कांट्रेक्ट डॉक्टर डॉ. जायसवाल और डॉ. लालचंदानी और एक विभागीय सीनियर डीएमओ डॉ. सुमीत प्रकाश कथित रूप से लगातार प्रयासरत हैं. इस महिला कांस्टेबल को इन डॉक्टरों के साथ उनकी कारों में भी घूमते आरपीएफ कर्मियों द्वारा जब देखा जाता है, तो उन्हें भारी शर्मिंदगी महसूस होती है. बताते हैं कि उक्त डॉक्टरों की मिलीभगत से अब तक निलेश उपाध्याय, पवन कुमार मिश्रा, एस. आर. पाईक, आर. के. जांगड़े, श्रीमती जयमाला बडगे, बी. पी. राठौर, जीतेंद्र कुशवाहा और आर. के. कश्यप आदि आरपीएफ कर्मियों को कथित तौर पर मोटी-मोटी रकम लेकर मेडिकली अनफिट किया जा चुका है. जबकि अभी इसी प्रकार से आरपीएफ कर्मियों और रनिंग स्टाफ को मेडिकली अनफिट किए जाने की लाइन काफी लंबी बताई जा रही है.

पता चला है कि उक्त महिला कांस्टेबल को कुछ दिनों पहले पैर में मोच आ गई थी, जिसके लिए वह एक विभागीय डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गई थी. इसी दौरान उसने मेडिकली अनफिट होने की योजना बनाई. इसके लिए उसने विभागीय डॉक्टर की सलाह पर सबसे पहले कमर दर्द (स्लिप डिस्क) का बहाना बनाया. सूत्रों का कहना है कि चूंकि इस महिला कांस्टेबल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसका पति भी आरपीएफ में ही इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, इसलिए उसे सीधे-सीधे अनफिट करने से पहले उसको हावड़ा स्थित पूर्व रेलवे के ओर्थोपैडिक हॉस्पिटल रेफर किया गया. सूत्रों के अनुसार विभागीय डॉक्टर ने ओर्थोपैडिक हॉस्पिटल में अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर को कहकर इस महिला कांस्टेबल को वहां से अनफिट करा लिया है. अब अंतिम तौर पर बिलासपुर केंद्रीय अस्पताल से इसको अनफिट किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

आरपीएफ स्टाफ का दावा है कि यदि एक रेलवे ड्राइवर, विभागीय डॉक्टर और दो कांट्रेक्ट डॉक्टरों के साथ पिछले दो-तीन महीनों से मोबाइल पर उक्त महिला कांस्टेबल की लगातार होने वाली बातचीत का रिकॉर्ड (कॉल डिटेल्स) निकाला जाए, तो सारी स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी. स्टाफ का यह भी कहना है कि यदि स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठन करके इस महिला कांस्टेबल की फुल मेडिकल जांच कराई जाए, तो इसको किसी प्रकार की स्लिप डिस्क नहीं होना प्रमाणित हो जाएगा. उनका यह भी कहना है कि यह अलग बात है कि जब कोई बार-बार स्लिप होगा, तो ऐसे में किसी को भी कमर दर्द होना स्वाभाविक है. उनका कहना है कि उसे गाड़ी में दौड़कर चढ़ते हुए देखा जा सकता है. 25-30 किमी. अप-डाउन करने में दर्द नहीं होता है. इसके बावजूद वह अक्सर अनुपस्थित रहती है, जिसका प्रमाणन इसकी उपस्थिति पंजिका देखकर किया जा सकता है.

इसके विपरीत एक अन्य महिला हेड कांस्टेबल नैना सिंह को मानसिक रोगी होने के चलते वास्तव में अनफिट किए जाने जहां वास्तविक जरुरत थी, वहां उसे करीब दो-ढ़ाई साल तक सिक में रखकर और इधर-उधर दौड़ाकर अंततः पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल स्थित जगजीवन राम हॉस्पिटल (जेआरएच) में भेजकर वहां से उसे फिट करा दिया गया. सूत्रों का कहना है कि यदि संबंधित डॉक्टर के कॉल डिटेल्स निकाले जाएं, तो जेआरएच में उसके द्वारा नैना सिंह को फिट किए जाने संबंधित बातचीत मिल सकती है. जबकि उसे भूलने सहित पागलपन के दौरे पड़ने जैसी गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ रहा है. सूत्रों का कहना है कि पैसा मांगे जाने पर नैना सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसकी समस्या असली है, इसलिए वह पैसा कदापि नहीं देगी. इसी वजह से उसे अंत तक परेशान करके अंततः जेआरएच से फिट करवाया गया, जिससे उसका आरोप बिलासपुर केंद्रीय अस्पताल के सीएमएस एवं अन्य डॉक्टरों पर न आए. इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि नैना सिंह को फिट कराने के मामले में पूर्व सीनियर डीएससी/बिलासपुर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

बताते हैं कि कांस्टेबल शेखर मंडल, जिसकी पसली बस से गिरने के कारण टूट गई थी, और वह सीधे खड़े होने तो क्या सीधा बैठने की भी स्थिति में नहीं था, फिर भी उसे फिट कर दिया गया. इसके अलावा हेड कांस्टेबल सी. के. राठौर, जिसके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है और वह एक टांग से लगभग बेकार हो चुका है, को अब तक सिर्फ इसलिए अनफिट घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि वह पैसा देने की स्थिति में नहीं है. जबकि आरपीएफ में आने के पहले से एक अन्य महिला हेड कांस्टेबल, जिसके घुटने में रॉड पड़ा हुआ था, को फिट करके आरपीएफ में ले लिया गया था. आरपीएफ में आने के बाद उसने उसी स्थिति में ट्रेनिंग भी पूरी की थी और अब तक सही-सलामत ड्यूटी कर रही थी. अब तक उक्त घुटने का न तो कोई ऑपरेशन हुआ और न ही कभी कोई विभागीय इलाज किया गया है, तथापि अब उसे सुनियोजित ढ़ंग से उक्त रॉड का कारण दिखाकर और फर्जी कागजात तैयार करके मेडिकली अनफिट करने की तैयारी चल रही है.

- पांच-सात साल की सर्विस वाले आरपीएफ जवानों को किया जा रहा है मेडिकली अनफिट
- पैसा न दे पाने वाले अनफिट होने के लिए दर-दर भटक रहे हैं वास्तविक जरूरतमंद जवान
- कांट्रेक्ट डॉक्टरों की मिलीभगत से विभागीय डॉक्टर चला रहे हैं फिट-अनफिट का गोरखधंधा
- पैसा दो-जब चाहे अनफिट हो जाओ, जब चाहे फिट होकर वापस पुराने विभाग में चले जाओ

एक चौंकाने वाली जानकारी यह भी मिली है कि कुछ समय पहले एक आरपीएफ स्टाफ इसी प्रकार पैसा देकर मेडिकली अनफिट हुआ था. बताते हैं कि मेडिकली डिकैटेगराइज होने के बाद कोरबा में उसकी पोस्टिंग बिलासपुर मंडल के एसएंडटी विभाग में की गई थी. जहां उसने लगभग 18 महीने काम भी किया था, मगर बताते हैं कि वह एसएंडटी में अपनी उक्त पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वहां उसको किसी प्रकार कोई चांस नहीं था. अतः वह मेडिकली फिट होकर पुनः आरपीएफ में आ गया और रूल-72 के तहत एएसआई की विभागीय परीक्षा भी दी. हालांकि उक्त परीक्षा में वह पास नहीं हुआ, मगर आरपीएफ में फिलहाल उसकी पोस्टिंग शहडोल, बिलासपुर मंडल में है. कहने का तात्पर्य यह है कि बिलासपुर केंद्रीय रेलवे अस्पताल से जब चाहे कोई भी अनफिट हो सकता है, जब चाहे फिट होकर पुनः अपने पुराने विभाग में जा सकता है. यह सारा खेल पैसे का है. इससे जाहिर है कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

स्टाफ का कहना है कि यह सब मोटी रकम के लेनदेन और आरपीएफ कर्मियों का खून चूसने का गोरखधंधा है, और इसके चलते अब तक पचासों आरपीएफ कर्मी मेडिकली अनफिट होकर डिकैटेगराइज हो चुके हैं. जबकि जिन आरपीएफ कर्मियों के पास डॉक्टरों को देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उन्हें डेढ़-दो साल तक सिक में रखकर और इधर-उधर दौड़ाकर फिट कर दिया जा रहा है. उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा पिछले तीन-चार सालों से बिलासपुर केंद्रीय रेलवे अस्पताल में चल रहे इस गंभीर फर्जीवाड़े को संज्ञान में लिया जाना जरुरी है. उन्होंने कहा कि जोनल मुख्यालय सहित रेलवे बोर्ड को भी इसका संज्ञान लेकर इस फर्जीवाड़े को रोका जाना चाहिए. कुछ जागरूक और वास्तविक जरूरतमंद बल सदस्यों ने इस फर्जीवाड़े के संबंध में रेलमंत्री, डीजी/आरपीएफ/रे.बो., डीजी/आरएचएस /रे.बो., विजिलेंस और डीआरएम/बिलासपुर सहित मुख्य चिकित्सा निदेशक, बिलासपुर को भी लिखित पत्र भेजे हैं, मगर अब तक उक्त सभी उच्चाधिकारियों की तरफ से इस गंभीर समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है. जबकि रनिंग स्टाफ का भी इसी फर्जीवाड़े की तर्ज पर बड़े पैमाने पर अनफिट और डिकैटेगराइज होने का गोरखधंधा चल रहा है. उल्लेखनीय है कि आरपीएफ और रनिंग स्टाफ सहित अन्य रेलकर्मियों को मेडिकली अनफिट करके डिकैटेगराइज करके क्लेरिकल में कमाऊ पदों पर पोस्टिंग कराने का यह गोरखधंधा लगभग सभी रेलों में चल रहा है. इसमें श्रमिक यूनियनों के कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं.

'रेलवे समाचार' द्वारा जब इस संबंध में सीनियर डीएमओ/ओपीडी डॉ. सुमीत प्रकाश से मोबाइल पर बात की गई, तो उनका कहना था कि किसी भी कर्मचारी को मेडिकली अनफिट किए जाने का एक मेडिकल बोर्ड होता है, जिसके सामूहिक निर्णय पर कर्मचारी को अनफिट किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस महिला कांस्टेबल श्रद्धा पांडेय की कमर में दर्द है, उसकी स्लिप डिस्क का अग्रवाल ओर्थोपैडिक हॉस्पिटल, हावड़ा ने किया है. उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि श्रद्धा पांडेय कभी उनकी कार में घूमने गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि महिला हेड कांस्टेबल नैना सिंह को जेआरएच ने फिट किया है. इस पर जब उनसे यह पूछा गया कि जब वह खुद एक सायक्याट्रिक स्पेशलिस्ट (मानसोपचार विशेषज्ञ) हैं, तब उसे जेआरएच में भेजे जाने की क्या जरुरत थी, वह भी दो-ढ़ाई साल तक इधर-उधर दौड़ाने के बाद, इस पर उनका कहना था कि यह निर्णय मेडिकल बोर्ड और सीएमएस द्वारा लिया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि एसआई आशुतोष तिवारी को हार्ट की समस्या थी. अस्पताल के एमडी डॉ. जी. के. चक्रवर्ती का कहना था कि फिट-अनफिट का सारा काम सीएमएस के मातहत होता है, इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते हैं.

इसके बाद जब 'रेलवे समाचार' ने अस्पताल के सीएमएस डॉ. पी. के. सरकार से बात की और उनसे यह पूछा कि उनके मातहत ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ कर्मियों और रनिंग स्टाफ को ही मेडिकली अनफिट और डिकैटेगराइज किए जाने का कारण क्या है? इस पर डॉ. सरकार का कहना था कि कोई न कोई कारण तो होता ही है. वैसे ही तो कोई डॉक्टर किसी कर्मचारी को अनफिट नहीं कर देगा. इस पर जब उनसे यह कहा गया कि मेडिकल लैंग्वेज में तो उनकी बात सही है, तो क्या इसी लिए वह किसी को भी पैसा लेकर अनफिट कर सकते हैं, कि मेडिकली उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है? इस पर उनका कहना था कि ऐसी बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड होता है, किसी एक डॉक्टर के कह देने मात्र से किसी कर्मचारी को अनफिट नहीं किया जाता है. मगर फिर भी पैसा लेने के आरोप लगते हैं, क्योंकि जेनुइन मामलों को दरकिनार करके संदिग्ध लोगों को अनफिट किया जाता है. इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. तथापि जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने ओपीडी में एक सायक्याट्रिस्ट को क्यों लगा रखा है, तब उन्होंने कहा कि अब उसे हटा दिया है. जबकि स्टाफ का कहना है कि डॉ. सरकार ने झूठ बोला है, क्योंकि डॉ. सुमीत प्रकाश (सायक्याट्रिस्ट) आज भी ओपीडी में ही तैनात हैं. इस सारे मामले में सीएमडी से संपर्क नहीं हो सका.

झांसी : झांसी मंडल पर उत्तर मध्य रेल पर मृतक रेल कर्मचारियों के आश्रितों को अंतिम भुगतान के प्रपत्र (पेमेंट एडवाइज तथा पेंशन पेमेंट ऑर्डर) देने के लिए 17 नवंबर को एक समारोह का आयोजन किया गया. उक्त समारोह में 13 परिवारों के आश्रितों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 9 आश्रित इस समारोह में शामिल हुए. झांसी के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अनिल कुमार छापोलिया ने उपस्थित आश्रितों को पेमेंट एडवाइज तथा पेंशन पेमेंट आर्डर वितरित किए. इस दौरान 88 लाख 81 हजार 507 रु. का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया गया. इस प्रकार का समारोह प्रत्येक महीने की 17 तारीख को किया जाता है. समारोह के अंत में अजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, उत्तर मध्य रेल, झांसी ने सभी का आभार व्यक्त किया.

डीआरएम को शिफ्ट करना समस्या का समाधान नहीं

सुरेश त्रिपाठी

पेज 1 का शेष...

सबसे कुप्रसिद्ध डीआरएम/रायपुर की अकर्मण्यता का परिणाम बताई जा रही है, जो अभी पंद्रह दिन पहले तक सबसे सुरक्षित और सर्वाधिक पन्क्चुअलिटी वाला डिवीजन होने की हांक लगा रहे थे, मगर इस घटना में पूरी की पूरी मालगाड़ी पलट जाने और लगभग पूरा दिन दोनों लाइनें ब्लॉक रहने से उनकी कार्य-क्षमता की सारी पोल खुल गई. इसके एक दिन पहले शनिवार, 19 नवंबर को तड़के भटिंडा-जोधपुर सवारी गाड़ी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाने के अंतर्गत प्रेमनगर गांव के पास डिरेल हो गई, जिसमें चार डिब्बे गिरे और 12 यात्री घायल हुए.

संयोग यह है कि ये तीनों रेल दुर्घटनाएं तब हुई हैं, जब हरियाणा के सूरजकुंड में रेलवे का महाकुम्भ 'रेल विकास शिविर' चल रहा था. जिस दिन पुखरायां दुर्घटना हुई, उस दिन यानि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री इस शिविर को प्रत्यक्ष संबोधित करने पहुंचे थे. पहले दिन 18 नवंबर को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करके इस कथित 'विकास शिविर' की औपचारिक शुरुआत करवाई थी. यह भी एक बड़ा संयोग है कि जिस दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन भी पूर्वोत्तर रेलवे के बस्ती-खलीलाबाद सेक्शन में एक बड़ी भीषण रेल दुर्घटना हुई थी. जिस प्रकार उक्त बड़ी रेल दुर्घटना की बाद में लीपापोती कर दी गई और एक एसएसई को निलंबित करके लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी, वाही हस्त्र अब पुखरायां रेल दुर्घटना का भी होगा.

हालांकि भारतीय रेल में आए दिन कहीं न कहीं रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मगर रेलमंत्री उनके बारे में कोई बयान देना जरुरी नहीं समझते रहे हैं. परंतु पुखरायां में हुई इंदौर-राजेंद्रनगर एक्स. की भीषण दुर्घटना पर उन्होंने न सिर्फ बयान दिया है, बल्कि अपना दुःख-दर्द जताने वह दुर्घटना-स्थल पर भी देर शाम को पहुंचे. रेलमंत्री ने दुर्घटना-स्थल पर मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि जांच के बाद जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ 'सट्रिक्टेस्ट' कार्रवाई की जाएगी. घटना-स्थल की हालत देखकर अपना दुःख-दर्द और आक्रोश व्यक्त करने के लिए रेलमंत्री को शायद हिंदी में इससे ज्यादा कड़ा कोई शब्द नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने इस मौके पर अंग्रेजी में एक नए शब्द की रचना कर डाली.

इससे पहले दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि घोषित करने की जैसे होड़ सी लग गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक होने के कारण सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह कहते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया कि यह घटना चूंकि उनके प्रदेश में घटित हुई है, इसलिए राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है. इसके बाद दुर्घटना-स्थल पर पहुंचे रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने शायद सही ही कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, तथापि उन्होंने रेलवे की तरफ से प्रत्येक मृतक के परिजन को 3.50 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार तथा मामूली रूप से घायलों को 25 हजार रुपए का मुआवजा घोषित किया. इसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहते हुए कि चूंकि उक्त गाड़ी इंदौर से चलती है, इसलिए मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख का मुआवजा घोषित किया जाता है. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका यह मुआवजा दुर्घटना में मृत हुए सभी मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा, या फिर केवल मध्य प्रदेश के उन यात्रियों को, जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से भी सभी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई. यानि इस तरह किसी रेल दुर्घटना में अपने किसी प्रियजन की जान गंवाना परिजनों के लिए फायदे का सौदा हो गया है?

इसके साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की दुर्घटना में मृतकों और उनके परिजनों के प्रति दुःख जताने और रेलवे की संरक्षा एवं सुरक्षा को कोसने की बयानबाजी और रश्म-अदायगी शुरू हो गई. सभी नेताओं ने कुछ न कुछ विशेष कहकर अपना दुःख जताया. मगर सबसे आपत्तिजनक बयान कानपुर के बुजुर्ग सांसद, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी का आया. उन्होंने अपना दुःख जताने के साथ-साथ यह भी कहा कि हो सकता है कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए यह कोई साजिश हो. सांसद डॉ. जोशी का यह बयान उसी तर्ज पर अत्यंत आपत्तिजनक है, जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर बलात्कार कांड को राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वह माफी मांगने को तैयार हैं.

- ऊरी हमले की तर्ज पर पुखरायां दुर्घटना के जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए
- रोड शो, प्रचार, विकास शिविर जैसी नई-नई नौटंकियों ने रेलवे को बना दिया असुरक्षित
- स्टोर की खरीद में सालाना पांच हजार करोड़ के हो रहे भ्रष्टाचार से सुपरिचित हैं सीआरबी
- शीर्ष पर 'स्टोरकीपर' की पुनर्नियुक्ति से हताश अधिकारियों में काम के प्रति पैदा हुई अरुचि
- परिजनों के लिए फायदे का सौदा हो गया है किसी रेल दुर्घटना में अपने प्रियजन की जान गंवाना
- सामने आ रहे हैं अधिकारियों को मुख्य कार्य के बजाय अनुत्पादक कार्यों में लगाने के दुष्परिणाम
- आजम खान की तर्ज पर सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान अत्यंत आपत्तिजनक है

पुखरायां के पास घटित हुई इंदौर-राजेंद्रनगर एक्स. की यह दुर्घटना शुद्ध रूप से तकनीकी और मानवीय लापरवाही का परिणाम है. तकनीकी रूप से इसलिए क्योंकि इंदौर से उज्जैन तक रोजाना इस गाड़ी से यात्रा करने वाले प्रकाश शर्मा नामक यात्री ने गाड़ी के चलने के कुछ देर बाद ही गाड़ी के ऑन बोर्ड स्टाफ को बताया था कि एस-1/2 कोच के एक्सेल और पहियों में जर्किंग जैसी हो रही है. मगर तब श्री शर्मा की बात को स्टाफ ने हवा में उड़ा दिया. इसके बाद इसी बात की सूचना झांसी में गाड़ी के ड्राइवर ने भी दी थी. इसी कारण से करीब 20 मिनट तक गाड़ी को झांसी में डिटेन भी किया गया था. परंतु जो ड्राइवर झांसी से उक्त गाड़ी को आगे ले जाने वाला था, उसे यह कहकर गाड़ी ले जाने को कहा गया कि कानपुर तक कैसे भी इसे लेकर जाओ, वहां इसकी जांच करने का मैसेज दे दिया जाएगा. जबकि झांसी में गाड़ी की पूरी जांच की जानी चाहिए थी और यदि किसी कोच का एक्सेल अथवा पहिया डगमग था, तो उसे काटकर अलग किया जाना चाहिए था, भले ही इस काम में चाहे जितना समय लगता, क्योंकि यात्रियों की जान से ज्यादा कोई समय कीमती नहीं हो सकता है.

कुछ तकनीकी जानकारों का मानना है कि उक्त गाड़ी के कुछ कोचों में फ्लैट टायर हो सकता है. उनका कहना है कि किसी कोच में फ्लैट टायर जरुर रहा होगा. यही वजह है कि उसकी सूचना उज्जैन के दैनिक यात्री ने स्टाफ को दी थी. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है और रफ्तार पकड़ती जाती है, वैसे-वैसे यह फ्लैट टायर बढ़ता जाता है. इसकी वजह से भी यह दुर्घटना हुई हो सकती है. इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि यदि किसी कोच में एक्सेल पुली लगी हुई है, यह एक्सेल पुली ढ़ीली होती है और कास्ट आयरन से बनी होती है. यह पुली कास्ट आयरन को काटती रहती है, यदि किसी एक्सेल पुली ने कास्ट आयरन को काट दिया, तो पहिया बाहर को चला जाएगा. ऐसी स्थिति में दुर्घटना तो होनी ही है. उनका यह भी कहना है कि यदि इस प्रकार की सूचना थी, तो झांसी के एसएसई/सीएंडडब्ल्यू/ऑन ड्यूटी को गाड़ी को आगे जाने ही नहीं देना चाहिए और अगर उसने ऐसा किया है, तो यह उसकी बहुत गंभीर चूक है, जिसका दुष्परिणाम 150 से ज्यादा मौतों और 300 से ज्यादा घायलों के रूप में सामने आया है.

इसके अलावा जानकारों का कहना है कि पुखरायां-मलाशा के बीच अवश्य पटरी में कहीं न कहीं दरार रही होगी, जिससे इंजन सहित दो-तीन डिब्बे तो सही-सलामत निकल गए, मगर 110 किमी. प्रति घंटे की गति से भागती गाड़ी का लोड उक्त दरार ज्यादा देर सहन नहीं कर पाई और पटरी टूट गई, जिससे पीछे के बाकी सभी कोच डिरेल हो गए. अत्यधिक गति होने के परिणामस्वरूप कुछ डिब्बे एक-दूसरे के अंदर घुस गए, जिसके फलस्वरूप ज्यादा मौतें हुईं और ज्यादा लोग घायल हुए. हालांकि यह बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है कि उक्त सेक्शन का अल्ट्रा-साउंड, डीप स्क्रीनिंग अथवा कम्पलीट ट्रैक रिन्यूवल (सीटीआर) कब हुआ था? तथापि इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह निकट विगत में तो नहीं ही हुआ होगा. इसके अलावा अब तमाम पीडब्ल्यूआई, जो कि अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर-पी-वे कहलाने लगे हैं, शायद ही अब कभी ट्राली करते हैं. ट्राली नहीं किए जाने से ट्रैक की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसी दौरान ट्रैक का अल्ट्रा-साउंड करके उसमें जहां तहां आने वाली संभावित दरारों का पता लगाया जाता है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विगत कुछ वर्षों से खरीदी जा रही रेलें भी कम गुणवत्ता वाली पाई गई हैं.

ज्ञातव्य है कि ठंड के मौसम में रेल सिकुड़ती है. और यदि जोड़ के पास पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई होती है, तो यह बकल (टेढ़ी-मेढ़ी) हो जाती है और साथ ही सिकुड़न की वजह से इन रेलों में दरारें भी पड़ती हैं. इसके विपरीत गर्मी के मौसम में रेल फैलती है. इसलिए ठंडी और गर्मी के मौसम में इन तमाम बातों का विशेष ध्यान रखते हुए सभी एसएसई/पी-वे और उनके संबंधित अधिकारी ट्रंक रेल रुट्स का खासतौर पर दैनिक निरीक्षण करते हैं. एक जेई/पी-वे ने 'रेलवे समाचार' को व्हाट्सऐप पर लिखकर भेजा है कि पुखरायां जैसी रेल दुर्घटनाएं तब तक नहीं रुक सकती हैं, जब तक कि सबसे निचले स्टाफ और सबसे ऊपरी अधिकारी को जिम्मेदार, जवाबदेह और उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा. उसका कहना है कि छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज किए जाने के परिणामस्वरूप ही बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं. उसका यह भी कहना है कि लोअर कैडर की वर्किंग में ट्रेड यूनियनों का अनावश्यक या अनधिकृत हस्तक्षेप रेलवे में भयंकर दुष्परिणामों का कारण बन रहा है. उसका यह भी कहा है कि अंततः जेई और एसएसई को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, मगर कोई भी ट्रैक मेंटेनर की ड्यूटी क्या है, यह पूछने तक की हिम्मत नहीं कर पाता है. उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे द्वारा 65 मीटर लांग रोल्ड रेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? यहां तक कि आज भी 13 मीटर और इससे भी कम लंबी रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई देखने-सुनने वाला नहीं है. उसका कहना है कि गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मटीरियल की उपलब्धता के बारे में तो अब रेलवे में सोचना भी गुनाह हो गया है. रेल दुर्घटनाओं के मामले में मटीरियल की खरीद में हो रहा भारी भ्रष्टाचार और इसकी अपर्याप्त उपलब्धता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है.

रेलकर्मी ही खुद बताते हैं और अक्सर विभागीय सेफ्टी सेमिनारों में इसका खुलकर बयान भी करते हैं कि कलपुर्जों और मटीरियल की कमी के कारण उन्हें गाड़ियों को अनसेफ या भगवान भरोसे भेजना पड़ता है. वह यह भी कहते हैं कि कई बार मेंटेनेंस के लिए आए हुए किसी कोच के कलपुर्जे निकालकर दूसरे कोच में लगालाकर उसे फिट करके भेजना पड़ता है. ऐसी स्थिति तब है जब एक 'स्टोरकीपर' (चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ए. के. मितल) खुद पिछले लगभग ढ़ाई साल से भारतीय रेल के शीर्ष पर बैठे हुए हैं. यही नहीं, रेलवे स्टोर की खरीद में सालाना पांच हजार करोड़ के हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी भी 'शीर्ष स्टोरकीपर' को है, क्योंकि वह जांच समिति के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं. शीर्ष में रहने के बावजूद उन्होंने उक्त समिति की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया है. इसे क्या समझा जाना चाहिए?

यदि ऊरी हमले के परिणामस्वरूप ब्रिगेड कमांडर को तत्काल बर्खास्त किया जा सकता है, जिसमें उसकी लापरवाही से कुछ सैनिकों की मौत हुई थी, तो जहां 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं और जिनके कारण 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उन्हें भी क्यों नहीं तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए? इस अपराधिक एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का हमेशा के लिए कैरियर बाधित किया जाना चाहिए. यदि इस तरह का कड़ा कदम, रेलमंत्री सुरेश प्रभु के शब्दों में सट्रिक्टेस्ट', उठाया जाता है, तो निश्चित रूप से संबंधित मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक, सीनियर डीईएन अथवा ब्रांच ऑफिसर्स, जो ट्रैक और कोचों का मेंटीनेंस देखते हैं, फिर कभी ऐसी अपराधिक लापरवाही नहीं करेंगे, और यात्रियों की संरक्षा-सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे. परंतु सिर्फ डीआरएम शिफ्ट कर देना और कुछ ब्रांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करना इस भीषण समस्या का कोई समुचित समाधान नहीं हो सकता है. यह तो सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकना और सारी घटना पर लीपापोती करना है.

देश की गति एवं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है भारतीय रेल : प्रधानमंत्री

सूरजकुंड में 3 दिवसीय रेल विकास शिविर आयोजित

गोरखपुर : भारतीय रेल को नई ऊँचाई देने के उद्देश्य से सूरजकुण्ड में 18 से 20 नवम्बर को आयोजित 3 दिवसीय रेल विकास शिविर के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेल देश की गति एवं प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है. वर्तमान शताब्दी तकनीक का युग है तथा हमें सामूहिक प्रयास से नए प्रयोग करते हुए भारतीय रेल को आधुनिकतम बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा. स्वयं को रेलवाला बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जुड़ाव बचपन से ही रेल से रहा है और वे रेल परिवेश में ही पले-बढ़े हैं. रेल के विकास से उन्हें भी उतनी ही संतुष्टि एवं हर्ष का अनुभव होगा जितना एक रेलकर्मी को.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अनुभव इस बात का साक्षी है कि किसी भी परिवर्तन के लिए दिल से आवाज उठनी चाहिए. ऐसा होने पर निःसन्देह सभी लोग मिलकर चिन्तन, मनन एवं कर्म कर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं. भारतीय रेल के सन्दर्भ में भी यह बात सत्य है. उन्होंने कहा कि इस रेल विकास शिविर की विशिष्टता यह है कि इसमें रेल से जुड़े जमीनी रेलकर्मियों से लेकर उच्च प्रबन्धन स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक साथ बैठकर रेल को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए विचार-विमर्श करेंगे. निश्चित रूप से रेल सेवा से लम्बे समय तक सम्बद्ध रेलकर्मियों का अनुभव बहुत ही व्यापक और व्यवहारिक होगा, जिसके फलस्वरूप चिन्तन प्रक्रिया से अनेक बहुमूल्य विचार सामने आएंगे, जिनके क्रियान्वयन से रेल निश्चित रूप से नई ऊँचाईयों तक पहुंचेगी. सामूहिक प्रयास एवं सहजीवन की महत्ता को रेखांकित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस चिन्तन शिविर में सभी एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होकर अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करेंगे, जिसका परिणाम बहुत ही लाभप्रद होगा. उन्होंने कहा कि रेल के विकास से देश और रेलकर्मियों का विकास सीधे जुड़ा हुआ है. रेल को विकसित कर रेलकर्मी न केवल देश हित में अमूल्य योगदान देंगे बल्कि उनका जीवन स्तर भी निश्चित रूप से सुधरेगा. मोदी ने कहा कि उनका यह सपना है कि रेल के निचले पायदान पर कार्य करने वाले रेलकर्मियों के बच्चों का भी भविष्य स्वर्णिम हो और यह तभी सम्भव है जब रेल सामर्थ्यवान होगी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस 3 दिवसीय चिन्तन प्रक्रिया से अनेक दुरगामी निष्कर्ष निकलेंगे, जिनका नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होगा.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने सम्बोधन में कहा कि पद सोपान रहित प्रकृति (नान हेरारिकल नेचर) के इस रेल विकास शिविर में रेल से जुड़े हर स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारियों की बराबर की सहभागिता होगी. यह चिन्तन शिविर नॉलेज बैंक के रूप में उभरकर सामने आएगा. उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेल को आधुनिकतम बनाने के सपने को पूरा करने में यह चिन्तन शिविर आधारशिला सिद्ध होगा.

रेल राज्यमंत्री एवं संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने अपने स्वागत सम्बोधन में रेल विकास शिविर की उपादेयता पर प्रकाश डाला. रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया.

उल्लेखनीय है कि इस रेल विकास शिविर में समस्त भारतीय रेल के 650 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया, जबकि वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 20 हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी चिन्तन शिविर में सहभागी रहे हैं.

टीम वर्क से ही रेलवे की क्षमता में होगी वृद्धि : सुरेश प्रभु, रेलमंत्री

गोरखपुर : सूरजकुंड, हरियाणा में आयोजित 3 दिवसीय रेल विकास शिविर के दूसरे दिन 19 नवम्बर को रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे की क्षमता में वृद्धि हेतु हम सभी को मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करना होगा. उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ ही यात्री एवं माल यातायात को और अत्यधिक तीव्र एवं सुगम बनाने की दिशा में यह शिविर काफी लाभदायक होगा. रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाकर लागत में कमी करने पर रेल मंत्री ने जोर दिया. प्रभु ने कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर अधिक से अधिक रेल परियोजनाओं को गति प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने से रेलवे का निजीकरण नही होगा बल्कि साफ-सफाई एवं खानपान आदि के क्षेत्रों में निजी भागीदारी से रेल राजस्व में वृद्धि होगी. रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल प्राइवेट सेक्टर/कारपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही हैं. सिविल सोसायटी एवं एनजीओ रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई एवं अन्य कार्यों को गति दे रहे हैं.

प्रभु ने कहा कि सभी रेलें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रेल राजस्व को प्राप्त करें. रेल मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम से निवेश के रूप में लगभग 1.50 लाख करोड़ प्राप्त किया है, जो रेल के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है. हमारा विकास भविष्य को देखते हुए होना चाहिए, न कि वर्तमान को. हमने यात्री पखवाड़ा का आयोजन सम्पूर्ण भारतीय रेल पर किया, जिसका हमें सकारात्मक परिणाम मिला. उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा जैसे राज्यों में पिछले बजटों की तुलना में चार गुना धन आबंटित कर वहाँ की लम्बित परियोजनाओं को गति दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं.

रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे के कार्यों में गति प्रदान करने हेतु पारदर्शिता एवं शक्ति का होना अति आवश्यक है. इसी उद्देश्य से हमने महाप्रबंधकों एवं मंडल रेल प्रबंधकों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियाँ प्रदान की हैं. मेरा यह मानना है कि स्टेशन मास्टरों को भी कुछ और पावर होना चाहिए, जिससे कि वे स्टेशन के विकास व यात्री सुविधाओं में सुधार कर सकें. रेलवे स्टेशनों के विकास एवं रेलवे के विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. सिस्टम को इन्टीग्रेट करने का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत महाप्रबंधकों एवं मंडल रेल प्रबंधकों के पदों के सिलेक्शन की प्रक्रिया को और न्यायसंगत बनाया जा रहा है. पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ रेल अभियान चलाया गया. रेल मंत्री ने कहा कि आम जनता से जुड़ने के लिए मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि शिविर में दिए गए सुझाव केवल सुझाव न हो बल्कि इस पर अमल भी होना चाहिए.

इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री एवं संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा एवं रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन सहित रेलवे बोर्ड एवं सभी क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाईकों के महाप्रबन्धक सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

हर हिंदुस्तानी के जीवन से जुड़ी है भारतीय रेल

रेल विकास शिविर के समापन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गोरखपुर : सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय रेल विकास शिविर के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय रेल के पास उत्तम मानव शक्ति, सोच एवं काम करने का संकल्प है तथा वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ है. प्रत्येक देशवासी को रेल का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः भारतीय रेल हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति के जीवन से गहराई से जुड़ा है. हम समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय रेल की प्रगति में उनकों अहम हिस्सेदार मानकर यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ताकत सवा सौ करोड़ गुना हो जाएगी. भारतीय रेल को देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल महज एक परिवहन व्यवस्था नहीं है बल्कि यह देश का प्रगति पथ है. टीम भावना एवं सामूहिक सोच की महत्ता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा भारतीय रेल एक टीम है तथा हम सभी रेल इंडिया के सदस्य है. हमें अपनी टीम शक्ति (समूह भावना) को पहचान कर बदलते हुए वैश्विक परिवेश में अपने उपयोगकर्ताओं तक सीधी और सहज कनेक्टिविटी स्थापित करें. कार्य संस्कृति को नई सोच के अनुसार विकसित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की विकास यात्रा में इनोवेट, रिनोवेट, मोटिवेट एवं कल्टीवेट ये चार बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण होंगे.

प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम इंदौर-पटना एक्सप्रेस के कानपुर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भारतीय रेल के विकास के लिए नए क्षेत्रों के अनुरूप कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार कर हम अपने उपयोगकर्ताओं से सीधा संबंध स्थापित करने में सफल होंगे. उन्होंने ग्राहकों का शेष पेज 7 पर...

प्रधानमंत्री द्वारा रेल सड़क पुल तथा दोहरीकरण का शिलान्यास...

पेज 1 का शेष... प्रभार) मनोज सिन्हा, राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, सांसद भरत सिंह, सांसद केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हरिनारायण राजभर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए. के. मित्तल, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे राजीव मिश्र एवं मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी एस. के. कश्यप समेत रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख अधिकारी एवं भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह भूमि वीर अब्दुल हामिद की है, जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया था. मैं यहां के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं की उन्होंने मुझ पर 2014 में विश्वास दिखाया. इस साल दूसरी बार गाजीपुर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. इस ट्रेन का नाम इसलिए 'शब्दभेदी' रखा गया है, क्योंकि आपको अपने इतिहास से भी जोड़कर रखना है, परंपरा से जोड़े रखना है. आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर पूरे भारतीय रेल पर विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आने वाले समय में रेल यातायात को और भी सुगम एवं जनोपयोगी बनाएंगी.

आरटीआई मैदान पर हुई प्रधानमंत्री की इस परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत और आखिर तक जनसमूह को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे. शुरुआत उन्होंने भोजपुरी से की. उनके मुंह से अपनी बोली सुनकर जनसमूह खुशी से झूम उठा. प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भारत माता का जयकारा लगवाया. फिर बोले- ई गाजीपुर राजा गाधि क नगरी ह. महर्षि विश्वामित्र अउरी जगदग्नि क नगरी ह. महान किसान नेता स्वामी सहाजानंद सरस्वतीजी एही गाजीपुर में पइदा भइलन. देश क आजादी खातिर डॉ. शिवपूजन राय सहित आठ शहीद भइलन. पैंसठ के युद्ध में पैटर्न टैंक के ध्वस्त करके पाकिस्तान क गुमान तोड़े वाले वीर अब्दुल हमीद एही धरती क सपूत ह. ए धरती के हम नमन करत बानी. एही धरती क गांव(गहमर) क पांच हजार जवान सेना में देश क रक्षा करेला.

इसके बाद वह मंचासीन रेलमंत्री सुरेश प्रभु, रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य. मानव संसाधन राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, सांसद के. पी. सिंह, सांसद हरिनारायण राजभर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद भरत सिंह, विधानदल के नेता सुरेश खन्ना, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, महामंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वाति सिंह, एमएलसी केदारनाथ सिंह, विधायक उपेंद्र तिवारी, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कृष्णबिहारी राय, जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह का नाम लिया. उन्होंने कहा कि दो साल के भीतर मुझे दूसरी बार गाजीपुर के लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा मैं लोकसभा चुनाव में 9 मई 2014 को गाजीपुर आया था. तब मैंने कहा था कि मेरा छोटा भाई (मनोज सिन्हा) चुनाव लड़ रहा है, आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे शब्द पर भरोसा किया, आपने न सिर्फ गाजीपुर से मनोज सिन्हा दिया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने देश में एक मजबूत नींव रखी है. अगर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने केंद्र में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनाई होती, तो आज भ्रष्टाचारी, कालेधन वाले चिंता में नहीं होता.

उन्होंने गाजीपुर के पूर्व सांसद स्व. विश्वनाथ सिंह गहमरी का याद करते हुए कहा कि उन्होंने संसद में गाजीपुर समेत पूर्वांचल की गरीबी की बात उठाई थी. उसे सुनकर पूरी संसद भावुक हो उठी थी. उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने पटेल कमेटी बनाई. कमेटी ने गाजीपुर में गंगा में रेल पुल की सिफारिश की, लेकिन वह योजना डिब्बे में बंद हो गई. पं. नेहरू भी चले गए. इस बीच कई प्रधानमंत्री आए और गए लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली. लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा- मैंने जानबूझकर दोबारा गाजीपुर आने का 14 नवंबर का कार्यक्रम बनाया. आज पं. जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन है. गंगा में रेल-सड़क पुल का शिलान्यास कर मैं पं.जवाहर लाल नेहरू के अधूरे कार्य को पूरा कर रहा हूं. मेरी तरफ से यह उनके लिए श्रद्धांजलि है.

कुल 48 मिनट के अपने भाषण में ऐसा कोई ऐसा नहीं आया जब जनसमूह का ध्यान प्रधानमंत्री के भाषण से इधर-उधर भटका हो. जनसमूह कई बार हर-हर मोदी, मोदी-मोदी के नारे लगा रहा था. बीच में एक बार मनोज सिन्हा ने जनसमूह को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि रहने दें, यह गाजीपुर के लोगों की गर्जना पूरा देश सुन रहा है. भाषण के अंत में जनसमूह से तालियां बजवाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा को याद कर मुझे आशीर्वाद दें. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान मंच पर मौजूद प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का नाम एक बार भी नहीं लिया. यह जरूर देखा गया कि मंच पर उनके साथ वह कानाफुसी करते नजर आए. इतना ही नहीं प्रोटोकाल में आए प्रदेश सरकार के पंचायतराज मंत्री रामगोविंद चौधरी का नाम लेने की भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी. इसके बजाय वह भाजपा जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह का न सिर्फ नाम लिया, बल्कि तीन बार उनकी पीठ भी थपथपाई.

इस अवसर पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि देश में पुल इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि यातायात में सहूलियत हो. लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए पुल काफ़ी जरुरी है. बीते कई वर्षों में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, उतना निवेश तीन वर्ष में कर दिया गया है. अब उत्तर प्रदेश को हर तरफ रेल मार्ग से जोड़ने के साथ ही यहां पर रेलवे की अधारभूत संरचनाओं समेत रेल का विस्तार किया जा रहा है. रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गाजीपुर को लहुरी काशी कहा जाता है. काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, विकास योजनाओं को गति देने के लिए, उनका स्वागत है. सरकार की मंशा के अनुरुप देश में विकास योजनाओं के लिए पुरानी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, मगर अब प्रदेश का विकास शुरु हुआ है.

रेल यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाजनक रेल परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय जनता की मांग को ध्यान में रखकर गाजीपुर सिटी-कोलकाता-गाजीपुर सिटी साप्ताहिक 'शब्द भेदी' एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है. इस गाड़ी के चलने से इस क्षेत्र की जनता को वाराणसी के रास्ते सीधे कोलकाता जाने-आने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यह गाड़ी गाजीपुर सिटी से प्रत्येक शुक्रवार को तथा कोलकाता से प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी.

प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ की गई मऊ-ताड़ीघाट नई लाइन परियोजना एवं गाजीपुर के समीप गंगा नदी पर रेल-सड़क पुल पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के उत्तर में स्थित कम विकसित क्षेत्र को दिल्ली-कोलकाता मेनलाइन से सीधे जोड़ने की चिरकाल से अपेक्षा रही है. मऊ-ताड़ीघाट नई लाइन परियोजान (51 किमी) का निर्माण इस आशा को पूरा करने वाला है. गाजीपुर के समीप गंगा नदी पर यह रेल-सड़क पुल परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है. इस परियोजना को सीसीईए द्वारा 1766 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जून 2016 में स्वीकृति मिली थी. यह परियोजना कार्यान्वित करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को दी गई है. इस रेल-सड़क पुल का निर्माण रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संयुक्त लागत से हो रहा है.

रेल विकास निगम लिमिटेड ने तीन माह की अल्प अवधि में पुल का तकनीकी डिजाइन, जियो-तकनीकी जांच तथा कार्य निर्माण की संविदा प्रदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस परियोजना से कई लाभ अपेक्षित हैं. यथा पूर्वांचल क्षेत्र, विशेषकर गाजीपुर में नए व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी. गाजीपुर से कोलकाता, गोरखपुर तथा देश के अन्य प्रमुख वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केंद्रों तक आवागमन के समय में कटौती भी होगी. यह कार्य संपन्न होने से किसी भी दिशा से आने वाली रेलगाड़ी के इंजन का घुमाव नहीं करना पड़ेगा. कोलकाता-मुगलसराय खंड का ट्रैफिक, जो भारी यातायात के कारण प्रायः धीमी गति से चलता है, बायपास करके सीधा गंगा नदी के उत्तर में पूर्वांचल क्षेत्र / उत्तर प्रदेश पहुंच सकेगा. इससे दिल्ली-कोलकाता मेनलाइन का ट्रैफिक भी सुगम हो जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों के लिए यह लाइन पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर की फीडर लाइन होगी. प्रधानमंत्री द्वारा उदघाटित पेरिशेबल कार्गो सेंटर, गाजीपुर घाट कुल 6.5 करोड़ रुपए की पूंजी से बनाया गया है. इस सुविधा के शुरु होने से निश्चित रुप से इस क्षेत्र के किसानों का आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. कॉनकोर ने कृषि उत्पादों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन पर एक पेरिशेबल कार्गो सेंटर (पीसीसी) का निर्माण किया है. यह सेंटर रेलवे की जमीन पर 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें सब्जियों के भंडारण हेतु 100 टन की क्षमता वाले चार चेंबर और फल पकाने वाले कुल 20 टन क्षमता के चार चेंबर हैं.

गाजीपुर जिला पूरी तरह से अपनी सब्जियों जैसे आलू, टमाटर, प्याज, मटर, मिर्च, फूलगोभी, हरी मटर, लौकी, भिंडी, कुम्हड़ा, पत्तागोभी आदि के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण, उत्पादित सब्जियों की एक बड़ी मात्रा यहां बर्बाद हो जाती है और छोटे किसानों को नुकसान होता है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता. इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में पेरिशेबल व्यवसाय को कोल्ड चेन के तहत कुशल रेल आधारित लॉजिस्टिक प्रबंधन करने के साथ छोटे एवं गरीब किसानों को फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान से बचाना तथा बेहतर कीमत मिलने की सुविधा को बढ़ावा देना है.

प्रधानमंत्री द्वारा गाजीपुर सिटी-बलिया रेल खंड के दोहरीकरण का भी शिलान्यास किया गया. वर्ष 2015-16 में 56.10 किमी. लंबे इस रेल खंड को 402 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत किया गया था. इस दोहरीकरण परियोजना को समयबद्ध तरीके से बलिया-फेफना (10 किमी.) वर्ष 2017-18, फेफना-युसूफपुर (35 किमी.) वर्ष 2018-19 तथा युसूफपुर-गाजीपुर सिटी (20.10 किमी.) वर्ष 2019-20 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है. बलिया-गाजीपुर सिटी दोहरीकरण परियोजना में 11 स्टेशन, 4 बड़े एवं 34 छोटे पुल, 34 समपार एवं 14 कर्व सम्मिलित हैं.

इस परियोजना का रुलिंग ग्रेडिएन्ट 1:400 है. पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल का छपरा-औड़हिार रेल खंड (173.04 किमी.) देश के पश्चिमोत्तर भाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है. द्वितीय कॉरीडोर के रुप में यह लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है. जल्दी ही इस रेल खंड का दोहरीकरण कर रेल परिवहन को सुगम बनाया जाएगा. बलिया से फेफना एवं गाजीपुर घाट से औड़हिार तक छोटी रेल लाइन के वर्ष 1899 में निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र में रेल अस्तित्व में आई थी. फेफना-गाजीपुर घाट में रेल लाइन बिछाने का कार्य 1903 में पूरा हुआ. यूनीगेज नीति के अंतर्गत छपरा-औड़हिार रेल खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन वर्ष 1996 में संपन्न हुआ था.

झांसी ने इलाहाबाद मंडल को 4-0 से हराया

अन्तर मंडलीय हॉकी चैम्पियनशिप-2016

इलाहाबाद. इलाहाबाद मंडल खेलकूद संघ के तत्वावधान में 17 से 19 नवंबर तक डीएसए ग्राउन्ड पर खेली गई अन्तर मंडलीय हॉकी चैम्पियनशिप-2016 में कुल 4 टीमों भाग ने भाग लिया. 17 नवंबर को हुए मुकाबले में इलाहाबाद मंडल ने झांसी वर्कशाप को 3-2 से हराया. 18 नवंबर को झांसी मंडल, आगरा मंडल को 4-0 से हराकर विजयी रहा. 19 नवंबर को फाइनल मैच इलाहाबाद मंडल एवं झांसी मंडल के बीच खेला गया, जिसमें झांसी मंडल ने इलाहाबाद मंडल को 4-0 से पराजित कर विजेता टीम घोषित हुई एवं इलाहाबाद मंडल उप विजेता रहा.

पुरस्कार वितरण अपर मंडल रेल प्रबन्धक, ए. के द्विवेदी के हाथों किया गया. इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियन्ता (समन्वय) एवं मंडल क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता, वरिष्ठ मंडल अभियन्ता (प्रथम) सचिन वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीलिमा श्रीवास्तव, सहायक मंडल क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक वाणिज्य प्रबन्धक एस.के. श्रीवास्तव, जहीरुद्दीन, पुष्पा श्रीवास्तव, एस.एन. मिश्रा एवं मंडल के बहुत से खिलाड़ी उपस्थित रहे.

चौबीस घंटों में भी एक्सीडेंट साइट...

पेज 1 का शेष... स्थल पर पहुंचना जीएम/द.पू.म.रे. ने जरूरी तक नहीं समझा.

बताते हैं कि घर पास होने की वजह से डीआरएम जल्दी ही दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गए थे. परंतु सारी वस्तुस्थिति जाने बिना ही डीआरएम ने पहला बयान यह दे मारा कि पिछली बार उरकुरा मामले में इंजीनियरिंग वालों की गलतियों को उन्होंने छिपा लिया था. इंजीनियरिंग वालों पर उनके ऐसे कई एहसान हैं. लेकिन उनकी बेइज़्ज़ती भी हुई जब बिल्हा से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को वह बचा लेना चाहते थे, पर कुम्हरी वाली दुर्घटना, जिसमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस गिरी थी, से बात बिगाड़ गई. इतना दबाव था कि उन्हें एक जूनियर स्केल अधिकारी को उसके लिए शहीद करना पड़ा था, वह भी तब जब उसका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था.

रविवार 20 नवंबर की सुबह 4.20 बजे जब मालगाड़ी गिरी, तब साइट में सबसे पहले हैवी क्रेन पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन डीआरएम ने ज़बरदस्ती एआरटी को साइट पर रखा और हैवी क्रेन को नहीं मंगवाया. अंततः 5 घंटे बरबाद करने के बाद एआरटी बिना कोई काम किए और बिना इंजीनियरिंग का सामान उतारे ही दुर्घटना स्थल से रवाना हो गई.

एक ओर डीईएन कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त लेबर नहीं हैं, दूसरी ओर ब्रेकडाउन स्टाफ ने कहा कि वह गिरे हुए माल डिब्बों को नहीं उठा पाएगा. ऑपरेटिंग अधिकारी के कहने के बाद भी उन्होंने क्रेन लाने नहीं दिया, क्योंकि डीईएन की बात सुनने को वह ज्यादा मजबूर थे. इस तरह उनकी मनमानी और तुगलकी व्यवहार के कारण दिन के उजाले के चार घंटे बरबाद हो गए.

इसके बाद डीआरएम साहब अपनी छतरी लगाकर उसके नीचे कुर्सी लेकर बैठ गए. साहब के लिए चाय मंगाई गई, नास्ता मंगवाया गया, साहब केले खाते हुए उसके छिलके इधर-उधर फेंकते रहे और बाकी अधिकारी एवं सारा स्टाफ काम पर लगा रहा. बाद में पुनः साहब के लिए समोसे और सैंडविच मंगवाए गए, जबकि सारा स्टाफ और अन्य अधिकारीगण ट्रैक की धुल खाते हुए ब्रेकडाउन ठीक करने में लगे रहे. फिर साहब के लिए गर्म कॉफी मंगवाई गई. इसके बाद पहला रिरेलमेंट हुआ और फिर साहब ने कहा मेरे आर्डर के बिना साइट पर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए. यह कहकर साहब फ्रेश होने के लिए घर चले गए. इस दरम्यान साहब नाराज़ न हो जाएं, साइट पर क्रेन का कोई मूवमेंट नहीं हुआ.

मजे की बात यह है कि साइट की पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद भी डीआरएम साहब साइट से करीब डेढ़-दो घंटे के लिए गायब हो गए. इतनी देर बाद वह लकदक कपड़े पहनकर पुनः साइट पर अवतरित हुए. इसके बाद उन्होंने दुबारा एआरटी को साइट पर लाने का आदेश किया, जिसका आना अब वाजिब था, क्योंकि 12 बजे तक जो होना था, वह सब किया जा चुका था. लेकिन डीआरएम साहब यह आदेश देकर सब भूल गए क़ि उनकी अनुमति के बिना साइट पर कोई मूवमेंट नहीं होगा. साहब के इस तुगलकी आदेश और अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग अधिकारी आपस में ही झिकझिक करते रहे.

अब साइट पर डीआरएम साहब के लिए स्पेशल खाना मंगवाया गया. उधर क्रेन के साथ सारा स्टाफ और अन्य अधिकारी बिना खाए-पिए ही दिन भर से काम में लगे हुए थे. सभी लोग साहब के इस ओछे व्यहवार को देखकर अत्यंत दुखी थे कि एक मुखिया कैसे एक्सीडेंट साइट पर खाने-पीने का मजा ले सकता है? खाने के दौरान वह कानपुर के पास पुखरायां-मलाशा के बीच इंदौर-राजेंद्रनगर एक्स. की भीषण दुर्घटना में मरने वालों की खबर ले रहे थे और खाते-खाते ही दुःख प्रकट करते जा रहे थे. खाने और दुःख जताने के बाद साहब ने साइट पर ब्रेकडउन स्टाफ पर यह कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि गैस कटर से सारे वैगन काट दो. अब साहब को यह कौन बताता कि स्टील से बने वैगनों को एक साधारण गैस कट्टर से नहीं काटा जा सकता है.

अब पता चला कि उरकुरा बाईपास को खाली रखने के लिए लांग-हॉल रेल चलाना ज़रूरी था, लेकिन डीआरएम साहब को मिक्स्ड पाथ का मतलब ही नहीं मालूम था, उन्हें तो साइट पर से किसी तरह जल्दी से जल्दी कोई सवारी गाड़ी चलाकर सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी थी. स्टाफ का कहना है कि डीआरएम साहब जिस तरह सबके सामने सीनियर डीओएम पर गला फाड़कर चिल्लाए, वह उनकी असुरक्षा एवं घटिया मानसिकता, हीनभावना और कमज़ोर नेतृत्व का परिचायक है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले रायपुर मंडल की संरक्षा-सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट 'रेलवे समाचार' ने 27 अक्टूबर को 'सैलून के व्यक्तिगत उपयोग से बचने के लिए डीआरएम/रायपुर की जोड़तोड़' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की है, जो कि आज भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

बैठ रहा है भारतीय रेल का भट्ठा...

पेज 1 का शेष... पैदा की जा रही है. उपरोक्त तीनों पद रेलवे बोर्ड मेंबर के समकक्ष हैं. इसलिए अब रेलवे बोर्ड मेंबर हो या महानिदेशक, उनमें कोई फर्क नहीं रह गया है. इसके अलावा जब उपरोक्त तीन पद समान हैं, और इनमें से डीजी/स्टोर्स और डीजी/एसएंडटी, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) के मातहत रखे गए हैं, यानि यह दोनों डीजी सीधे सीआरबी को रिपोर्ट करेंगे, जैसे अब सभी जोनल महाप्रबंधक कर रहे हैं, तो सिर्फ डीजी/कार्मिक को ही अकेले मेंबर स्टाफ, रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करने को क्यों कहा गया है? यानि डीजी/कार्मिक को मेंबर स्टाफ के मातहत क्यों रखा गया है? इसका कोई वाजिब जवाब रेलवे बोर्ड अथवा उसके एडीजी/पीआर के पास नहीं है. रेलवे बोर्ड के विश्वसनीय सूत्रों ने 'रेलवे समाचार' को बताया कि डीजी/कार्मिक को मेंबर स्टाफ के मातहत रखने के लिए यह घटिया सा तर्क दिया गया है, कि चूंकि डीजी/आरपीएफ और डीजी/आरएचएस मेंबर स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं और अब तक एडीशनल मेंबर/स्टाफ भी मेंबर स्टाफ को ही रिपोर्ट करते रहे हैं, इसलिए डीजी/कार्मिक को मेंबर स्टाफ के मातहत रखा गया है. परंतु ऐसा घटिया और अमान्य तर्क किसी के भी गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि इससे समान ग्रेड और समान ओहदा होने के बावजूद डीजी/कार्मिक का कद कम किया गया है. इसी प्रकार एडीशनल मेंबर/सीएंडआईएस को मेंबर ट्रैफिक के नीचे से निकालकर मेंबर स्टाफ के मातहत किए जाने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया है. रेलवे बोर्ड के कुछ समझदार और समर्पित अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार सिर्फ स्टोरकीपर सीआरबी और मेंबर स्टाफ, जो कि किसी लायक नहीं हैं, को ही रेलवे बोर्ड में मजबूत किया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल का भट्ठा लगातार बैठता जा रहा है.

पुखरायां-मलासा रेल हादसा

युद्ध स्तर पर किया गया राहत एवं बचाव कार्य

उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल के झांसी-कानपुर के मध्य पुखरायां-मलासा स्टेशन के निकट इंदौर-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरने तथा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 150 रेल यात्रियों की मृत्यु एवं 181 यात्री घायल हुए। रेल प्रशासन द्वारा इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए एआरटी, टावर वैगन तथा एआरएमई वैन (एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट) इलाहाबाद-कानपुर-आगरा एवं झांसी से तत्काल रवाना की गई, जिसमें 24 डाक्टर, 31 पैरा मेडिकल स्टाफ भी रवाना किए गए. प्रधान कार्यालय से मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सहित झांसी मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक, इलाहाबाद मंडल के अपर मंडल रेल प्रबन्धक, उप मुख्य यातायात प्रबन्धक, कानपुर एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर कराया। महाप्रबन्धाक उत्तर मध्य रेलवे अरूण सक्सेना ने घटना स्थल पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ घायल यात्रियों को हरसम्भव चिकित्सीय सहायता, आर्थिक सहायता एवं हर सम्भव सहायता प्रदान किये जाने की

निगरानी कर रहे थे। भारतीय सेना, वाराणसी एवं लखनऊ से आयी एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी थीं। दुर्घटना स्थथल पर प्राथमिक चिकित्सी भी प्रदान की जा रही थी। रेलवे की एम्बुलेंस सहित लगभग 50 एम्बुलेंस प्रभावित यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों/नर्सिंग होम तक पहुंचा रही थी।

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा घटना स्थल/प्रधान कार्यालय में प्रेस एवं मीडिया को अद्यतन समाचार, रेल गाड़ियों के निरस्तीनकरण/ मार्ग परिवर्तन, घायल एवं मृत रेल यात्रियों के संबंध में सूचना देने हेतु लगातार प्रेस ब्रिफिंग एवं प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती रही। उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा इस मुश्किल अवसर पर भी कठिन से कठिन चुनौतियों के उपरांत, जान-माल की हानि को कम से कम करने हेतु कार्य किया। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा किए गए अथक प्रयासों से 21 नवंबर को सायं 17.00 बजे तक ट्रैक क्लियर कर दिया गया तथा 23.20 बजे पहली मालगाड़ी को चलाया गया, जिसके उपरांत यात्री गा ड़ियों का आवागमन प्रारम्भ कर दिया गया।

हर हिंदुस्तानी के जीवन से जुड़ी है भारतीय रेल ...

पेज 5 का शेष... इंतजार करने की जगह ग्राहकों तक स्वयं पहुंचने की सलाह दी. भारतीय रेल प्रणाली में जनता का विश्वास पुष्ट करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने ग्राहकों की मानसिकता को सही संदर्भों में समझने को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया. प्रधानमंत्री ने रेल विकास शिविर के दौरान चुने गए 5 बेहतरीन सुझावों एवं 3 बेहतरीन टीमों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री की भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं कायाकल्प के सपने को साकार करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है. इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इस 3 दिवसीय रेल विकास शिविर का आयोजन किया गया तथा इसके पूर्व लगभग दो माह का समय अनेक स्तरों पर सुधारात्मक उपाय हेतु चिन्तन एवं मनन में दिया गया. उन्होंने कहा कि संगठन में बदलते समय के अनुसार अपेक्षित बदलाव करके ही हम प्रगति के नए आयाम प्राप्त कर सकेंगे.

इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए.के. मितल ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर ही भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार रेल विकास शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हर स्तर के रेलकर्मियों ने रेल के विकास हेतु अपने सुझाव दिए. इस शिविर में 38 ग्रुपों में 8 थीम पर गहन विचार-विमर्श किया, जिनसे आज पावर प्वाइंट प्रजेनटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि 24 विचारों को शार्टलिस्ट किया गया है तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु वर्गीकृत भी किया गया है. रेल मंत्रालय स्तर पर एक विशेष सेल बनाकर इन नए विचारों को कार्यान्वित करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है. इसके पूर्व, रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने अपने स्वागत सम्बोधन में रेल विकास शिविर की उपादेयता पर प्रकाश डाला. उन्होंने सभी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया.

चालू वित्तवर्ष की पहली छमाही में रेलवे की आय में...

पेज 1 का शेष... है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 4.04% कम है। गत वित्तवर्ष 2015-16 की पहली छमाही में भारतीय रेल की कुल आय 79,475 करोड़ रुपए हुई थी।

यह जानकारी देते हुए रेल राज्यमंत्री राजन गोहाईं ने बताया कि गत वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में रेलवे की कुल आय 79,475 करोड़ रुपए हुई थी, जो कि चालू वर्ष 2016-17 में घटकर 76,266 करोड़ रुपए हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की आय में कमी की प्रमुख वजह माल भाड़े में कमी किया जाना रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक मालभाड़े से रेलवे को 52,771 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। जबकि चालू वर्ष 2016-17 में 1 अप्रैल से 16 सितंबर तक यह आमदनी घटकर 47,974 करोड़ रुपए पर आ गई है। यानि मालभाड़े की आय में चालू वर्ष की पहली छमाही में कुल 9.09% की कमी आई है।

इसका मतलब यह है कि मालभाड़े में लगातार आ रही गिरावट की वजह से देश का दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भारतीय रेल लगातार घाटे की गर्त में समाती जा रही है। रेल राज्यमंत्री ने खुद कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल रेलवे ने 8.67 मिलियन टन माल कम ढ़ोया है।

यदि जोनल रेलों के अनुसार रेलों की आय को देखा जाए तो मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे जोन भारी घाटे में हैं।

इस साल सबसे ज्यादा घाटे में पश्चिम रेलवे है। दक्षिण मध्य रेलवे को 787 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जबकि पश्चिम मध्य रेलवे का घाटा 762 करोड़ रुपए है। जबकि पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो की आय इस साल बढ़ी है। उत्तर रेलवे को 466 करोड़ रुपए की आय हुई है।

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618 प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित ■ POST Regd. No. THC/135/2015-2017

जखनियां स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का शुभारंभ

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के हाथों उद्घाटन

जखनियाँ : रेल राज्यमंत्री एवं संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने जखनियाँ स्टेशन पर 26 नवम्बर को आयोजित एक समारोह में नवीनीकृत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया. इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जखनियाँ रेलवे स्टेशन पर 3 करोड़ की लागत से उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. प्लेटफार्म संख्या एक का विस्तारीकरण सतह में सुधार किया गया है. प्लेटफार्म संख्या 2 का विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा. स्टेशन भवन में सुधार कर इसे आकर्षक बनाया गया है. स्टेशन पर एक पैदल उपरिगामी पुल बनाया गया है. स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया एवं पार्क को विकसित किया गया है. महिला एवं पुरुष यात्रियों के लिए अलग-अलग वेटिंग रूम बनाया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने के साथ यात्री युविधाएं प्रदान की गई है.

सिन्हा ने कहा कि औडिहार-भटनी, औड़िहार-जौनपुर, मऊ-शाहगंज एवं इन्दारा-फेफना खण्डों का विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण का कार्य चल रहा है. इसके साथ ही दोहरीघाट से सहजनवा तक नई रेल लाइन को मंजूरी दी गयी है. ताड़ीघाट-गाजीपुर-मऊ नई रेल लाईन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है. छपरा-वाराणसी-इलाहाबाद खण्ड के विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से तेजी से चल रहा है. सभी परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि रेल के आधारभूत ढाँचें को मजबूत कर रेल परिवहन प्रणाली को प्रभावी, द्रुतगामी तथा जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाय. इसी क्रम में आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, नई लाइन निर्माण, विद्युतीकरण, उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित अनेक दूरगामी परिणाम देने वाले कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं.

इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद डॉ. केदार नाथ सिंह, सदस्य विधान परिषद विजय कुमार यादव एवं सदस्य विधान परिषद विशाल सिंह ने जखनियाँ रेलवे स्टेशन पर नवीनीकृत यात्री सुविधाएं के उपलब्ध कराये जाने पर माननीय रेल राज्य मंत्री एवं संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार मनोज सिन्हा को साधुवाद दिया.

अतिथियों को स्वागत करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबन्धक एस. एल. वर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे अपने सम्मानित यात्रियों को उत्कृष्ट यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में जखनियाँ स्टेशन पर लगभग 3 करोड़ की लागत से उन्नत यात्री सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है. वर्मा ने कहा कि जखनियाँ स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या एक का विस्तार एवं इसके सतह में सुधार किया गया है. स्टेशन पर पुरुष एवं महिला यात्रियों के लिये वेटिंग रूम बनाये गये हैं. पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प लगाये गये हैं. यात्रियों को धूप एवं वर्षा से बचाने के लिये 10 छोटे ऊंचाई के यात्री छाजन तथा बैठने हेतु आरसीसी बेन्चों का निर्माण किया गया है. एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने हेतु पैदल उपरिगामी पुल बनाया गया है. स्टेशन भवन को आकर्षक स्वरूप दिया गया है. इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील के बेंच उपलब्ध कराये गये हैं. अपर महाप्रबन्धक वर्मा ने कहा कि यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से अनारक्षित यात्रा टिकट उपलब्ध कराने के लिये ए.टी.वी.एम. लगायी गयी है. स्टेशन पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. लाईट का प्रावधान किया गया है. इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने से यहां आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

मंडल रेल प्रबन्धक/वाराणसी सतीश के. कश्यप ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/वाराणसी आलोक कुमार सिंह समारोह का संचालन किया.

दीनदयालु कोच युक्त नई गाड़ी की शुरुआत

इलाहाबाद : उत्तर मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी सं 14117/14118 इलाहाबाद-बस्ती एक्सप्रेस दीनदयालु कोच युक्त नई गाड़ी (सप्ताह मे 5 दिन- गुरुवार एवं रविवार को छोड़कर) की शुरुआत बुधवार, 30 नवंबर 2016 को की गई. इस गाड़ी का नियमित परिचालन शुक्रवार, 2 दिसंबर 2016 से प्रारंभ किया जाएगा.

रवींद्र गुप्ता बने नए मेंबर रोलिंग स्टॉक, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली : अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) ने सोमवार, 21 नवंबर को इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (आईआरएसएमई) वर्ष 1980 बैच के मैकेनिकल अधिकारी रवींद्र गुप्ता के नाम का क्लियरेंस दे दिया है. श्री गुप्ता 1 दिसंबर से मेंबर रोलिंग स्टॉक, रेलवे बोर्ड का पदभार संभाल लेंगे. वर्तमान में श्री गुप्ता दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के महाप्रबंधक हैं. श्री गुप्ता 31 जुलाई 2018 तक उक्त पद पर रहेंगे. उल्लेखनीय है कि वर्तमान मेंबर रोलिंग स्टॉक हेमंत कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसके साथ ही रवींद्र गुप्ता से सीनियर चार महाप्रबंधकों को एसीसी ने एनएफ-अपेक्स स्केल (मेंबर रेलवे बोर्ड के समकक्ष) दिए जाने की भी मंजूरी दी है. इनमें उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. पुठिया, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जी. एस. अग्रवाल और दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक वशिष्ठ जौहरी को नॉन-फंक्शनल अपेक्स स्केल मंजूर किया गया है. इन चारों महाप्रबंधकों के लिए यह अपेक्स स्केल उस दिन (1 दिसंबर, 2016) से लागू होगा, जिस दिन रवींद्र गुप्ता रेलवे बोर्ड में बतौर मेंबर रोलिंग स्टॉक ज्वाइन करेंगे.

ए.के.पुठिया, राजीव मिश्रा, जी.सी.अग्रवाल और वशिष्ठ जौहरी को एनएफ-अपेक्स स्केल

भारतीय रेल लेखा सेवा दिवस का आयोजन

इलाहाबाद : 26 नवम्बर 2016 को आईआरएएस दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय इलाहाबाद में एक संगोष्ठी वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे जे. पी. पाण्डेय एवं वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी, रेल विद्युतीकरण गीतिका पाण्डेय की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में उत्तर मध्य रेलवे एवं रेल विद्युतीकरण के सभी अधिकारी शामिल हुए। हाल के पुखरायां रेल हादसे को देखते हुए सादगीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जे. पी. पाण्डेय, वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी उत्तर मध्य रेलवे ने की।

योगेश श्रीवास्तव वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी/वित्त एवं सामान्य ने आईआरएएस के इतिहास पर प्रकाश डालकर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इसके पश्चात जीएसटी की बारीकियों एवं रेलवे पर इसके प्रभाव विषय पर 'हबीबुल्लाह एंड कंपनी' ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। युवा एवं वरिष्ठ अधिकारियों दोनों ने अपनी सेवा को बेहतर बनाने एवं आने वाली चुनौतियों से निपटने के सुझाव दिए।

चर्चा के दौरान सभी अधिकारियों द्वारा आईआरएस सेवा को व्यावसायिक सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी/रेल विद्युतीकरण गीतिका पाण्डेय ने सभी को अपनी अंतरात्मा में झांकने एवं अपने ज्ञान और कौशल को लगातार अद्यतन रखने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में वित्त सलाहकार मुख्य लेखाधिकारी उत्तर मध्य रेलवे जे. पी. पाण्डेय ने अपनी सम्पूर्ण सेवा के अनुभवों को साझा किया एवं सभी को पूरी लगन एवं सत्यनिष्ठा से रेल के हित एवं विकास में कार्य करने की प्रेरणा दी।

आजीवन सदस्यता 3000 रु.
संरक्षक सदस्यता 5000 रु.
कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार
रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी
संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस,
पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास,
कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. 09869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक - सुरेश त्रिपाठी

● इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
● गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
● भुसावल : शेख सत्तार ☎ 09370615244
● रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 09427484069
● वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 09824016464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017